

खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य-योजना

*602. श्री राम जेटमलानी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से समय-समय पर कार्य योजना तैयार करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान बनाई गई इस तरह की विभिन्न कार्य-योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) उनके माध्यम से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

युवा कार्य और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार देश में खेलों के संवर्धन के लिए, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करती है। योजना राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से अपेक्षा के अनुसार सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(ग) अवस्थापना का सृजन, राष्ट्रीय खेल परिसंघों आदि को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए लाभान्वित होने वाले लोगों की सही संख्या बताना बहुत ही कठिन है क्योंकि लाभ समाज के एक बड़े वर्ग को प्राप्त होता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान मंत्रालय/भारतीय खेल प्राधिकरण की कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित खिलाड़ी निम्नलिखित हैं:—

क्र०सं०	योजनाओं का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम	215
2.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	971
3.	सेना बाल खेल कंपनियां	691
4.	विशेष क्षेत्र खेल	1048
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र	4042
6.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना	8986
7.	खेल विज्ञान/चिकित्सा केन्द्र तथा अनुसंधान छात्रवृत्ति	18585

क्र.सं०	योजनाओं का नाम	लाभार्थियों की संख्या
8.	तकनीकी खेल उपस्कर का केन्द्रीय पूल	4042
9.	इंदिरा गांधी स्टेडियम	24576
10.	उत्कृष्टता केन्द्र	306
11.	अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट	2118
12.	उत्तर-पूर्वी खेल महोत्सव	989
13.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव	2389
14.	खेल छात्रवृत्ति योजना	6425
15.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष पुरस्कार	231
16.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	50
17.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल कोष	227
18.	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	1
19.	अर्जुन पुरस्कार	23
कुल योग:		75,875

Action plan for promoting sports

†*602. SHRI RAM JETHMALANI: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that action plan is prepared by Government from time to time for promoting sports in the country, through the Sports Authority of India;

(b) if so, the various types of such action plans prepared during the year 2000-2001; and

(c) the number of people benefited through them?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) and (b) Government prepares an Action Plan for implementing various schemes and programmes for promoting sports in the country. The plan is implemented by Government and through SAI, in consultation with National Sports Federations as required.

(c) The exact quantification of people benefited through schemes such as Creation of Infrastructure, Assistance of National Sports Federations etc. is extremely difficult to work out as the benefit accrues to a large section of society. The sports persons benefited directly under some of the schemes of the Ministry/SAI during 2000-01 are as under:

Sl. No.	Name of the Schemes	No. of Beneficiaries
1	2	3
1.	Physical Education Programme	215
2.	National Sports Talent Contest	971
3.	Army Boys Sports Companies	691
4.	Special Area Games	1048
5.	SAI Training Centres	4042
6.	National Coaching Scheme	8986
7.	Sports Science/medical Centre & Research Scholarship	18585
8.	Central Pool of Technical Sports Equipment	4042
9.	IG Stadium	24576
10.	Centres of Excellence	306
11.	All India Rural Sports Tournament	2118
12.	North East Sports Festival	989
13.	National Sports Festival for Women	2389
14.	Sports Scholarship Scheme	6425
15.	Special awards to winners in International Sports events	231
16.	National Welfare Fund for Sports Persons	50
17.	Sports Fund for Pension to Meritorious Sports Persons	227

1	2	3
18.	Rajiv Gandhi Khel Ratna Award	1
19.	Arjuna Awards	23
GRAND TOTAL:		75,875

SHRI RAM JETHMALANI: Mr. Chairman, Sir, I do not want to sound pessimistic. We are going to host the Afro-Asian Games, I believe, sometime in November. Very little time is left. In the meantime, Sir, the newspaper reports, particularly from very perceptive sports correspondents, are very, very disturbing. For example, one of the sports commentators has summarised the situation by saying, "No knowledge, no vision, no plan, no will." Sir, it is even my personal observation that your tracks in the various stadia in the city are completely like bombed craters. Sir, the roofs are leaking like those torn umbrellas of our slum dwellers in Bombay. And, the only major swimming pool is supposed to be having contaminated water supply and it has gone below the international standards. Sir, the anxiety today is that we are out for a big international fiasco. I want to ask the hon. Minister whether she is aware of this widespread anxiety, whether she has analysed the causes of this anxiety, and whether she is prepared to assure this House that this anxiety is unfounded and nothing will go wrong, because of any lack of organisational capacity or infrastructure.

सुश्री उमा भारती: सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करती हूँ। इन्होंने किसी न्यूज पेपर की रिपोर्ट का हवाला दिया है और विजन, नॉलेज और विल इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने यह कहा है कि ये तीनों ही एफ्रो एशियन गेम्स की तैयारियों में नहीं दिख रही हैं। ऐसा किसी रिपोर्ट का उन्होंने उल्लेख किया है। विजन, नॉलेज और विल का जबाब होता है डिटरमिनेशन। एक बार जब यह फैसला हो चुका है कि तीन नवम्बर से हमें एफ्रो एशियन गेम्स होल्ड करने हैं और यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमको यह फैसला सुनाया कि यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और इन गेम्स को पोस्टपोंड नहीं करना है बल्कि ये गेम्स करने हैं। उसके बाद मेरी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि ये खामियां हैं। यद्यपि न्यूज पेपर रिपोर्ट में कुछ अतिशयोक्ति होगी, हम उन खामियों को समय रहते दूर कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मेरी इस संबंध में विभाग के अधिकारियों से बैठक में चर्चा

हुई है और वे इस बात को लेकर विश्वस्त हैं, उनके अंदर यह आत्मविश्वास है कि वे इन खामियों को दूर कर सकेंगे।

सर, यद्यपि एक कठिनाई है जिससे मैं इस सदन को अवगत करना चाहती हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे इस सदन को विश्वास दिलाना है और सदन के माध्यम से देश को विश्वास दिलाना है कि एफ्रो एशियन गेम्स को हम कर सकेंगे या नहीं। इसमें हमारी और मंत्रालय की जिम्मेदारी तीन तरह की है। हमारे मंत्रालय की पहली जिम्मेदारी इनफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की है। दूसरी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के खिलाड़ी इसमें मेडल जीतकर आये और हम उसके लिए तैयारी करेंगे। तीसरी जिम्मेदारी है कि उसके बाद राज्य सभा और लोक सभा में जो हमसे पूछा जायेगा उसका उत्तर देना है। सर, हम इन तीनों जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक कठिनाई है जो हमारे हाथ में नहीं है वह अगर आयेगी तो हम उसको भी पार करेंगे इसलिए हम उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। वह कठिनाई इंद्र देवता की है, मानसून की है और मानसून की वजह से हम उन तिथियों के आगे पीछे के दिन भी कुछ एडिशनल अपने लिए रखेंगे। उस कठिनाई को पार करने के लिए कौन सा रास्ता निकालें उसके बारे में हम सब सोच रहे हैं। मैं इस सदन को आश्वासन करना चाहती हूँ कि एफ्रो एशियन गेम्स इस देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारा मंत्रालय विजन, नॉलेज और विल इन तीनों को लेकर नहीं करता है बल्कि एक चौथी चीज भी हमारे पास में है और वह है डिटरमिनेशन और उस डिटरमिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। हम देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप खेलों का आयोजन कर के दिखा देंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Thirunavukkarasu.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have to put my second supplementary. Sir, my second supplementary is, it is increasingly being observed that whenever politicians, particularly full time politicians, are getting into these sports organisations, the result is chaos. And the latest illustration, Sir, is football. It is going to become a huge scam very soon. Sir, I welcome sports being injected into politics, but I want to ask the hon. Minister whether she has any plans to see that politics are kept out of sports altogether. And, Sir, recently the controversy that has gone on between Shri Muthiah, President of the BCCI and the Minister, is unfortunate. All that the Board wants to know is whether you have a definite policy about playing with Pakistan. It is not enough merely to say that cricket stands on a different footing. Why cricket stands on a different

footing? Why does cricket stands on a different footing? Recently, Gopichand won the All-England Badminton Championship. So, why is badminton not important? Why is wrestling not important? Why is hockey not important? This kind of tension that is going on between the Board and the Ministry is unwarranted. Will the Minister give us some assurance that there would be a clear-cut policy about playing with Pakistan so that these controversies do not go in public?

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य ने जो पहली बात कही है, खेल संघों से राजनैतिक दखलअंदाजी कम करने की, क्योंकि राजनैतिक दखलअंदाजी के चलते खिलाड़ियों को बहुत दिक्कतें आती हैं और खेल संघ भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर एकाग्र करने के बजाय अपनी लड़ाइयों में ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति और सरकार का दखल—ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप को हम अपनी तरफ से कैसे कम कर सकते हैं? हम सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम करते हैं और खेल संघों की स्वायत्तता बनी रहे, इस संबंध में हम खेल संघों के साथ पूरा सहयोग का वातावरण बनाए रखते हैं। अब रही खेल संघों में राजनैतिक हस्तक्षेप की बात तो महोदय, कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति में भी हैं और खेल संघों में भी हैं। हम उनको खेल संघों के पदाधिकारी होने से नहीं रोक सकते हैं। खेल संघों की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें हम तब तक दखल नहीं दे सकते हैं जब तक हमें यह न लगे कि वह अपनी सीमाओं को पार कर गये हैं और हमारी दखलअंदाजी की जरूरत पड़ गयी है। मैं इस सदन में सबको निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा प्रयास इस दिशा में हो और मैं कोड ऑफ कंडक्ट लाने के बारे में बहुत दिनों से विचार कर रही हूँ। हमने भारत के सभी राज्यों के खेल मंत्रियों की बैठक बुलायी थी। उनके सामने हमने कोड ऑफ कंडक्ट का प्रस्ताव रखा था। अब हमारा दूसरा स्टेप है फेडरेशंस की बैठक बुलाने का, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए उनका भी परामर्श लेने का। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम जबर्दस्ती उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें। हम उनकी भी सहमति लेंगे और अगर उसमें वह कोई परिवर्तन करना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे तो हम वह भी करेंगे। यह सर्वोच्च सदन है और मैं इस सदन में यह निवेदन करूंगी कि इस मामले में कोड ऑफ कंडक्ट और कन्करैस में खेल आ जाए क्योंकि कन्करैस में खेल नहीं होने के कारण उनको बहुत कठिनाइयां आएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी हमको कठिनाइयां आएंगी इसलिए मैं इस सदन को निवेदन करूंगी कि हमें अधिकांश राज्यों की सहमति कन्करैस के लिए मिल गयी है। अब हमें सदन की सहमति, सदन में जो पार्टियां हैं, लोक सभा और राज्य सभा में जो लोग हैं, उनकी सहमति इसके लिए चाहिए। अगर हमें वह सहमति मिल जाए तो हम खेल संघों से राजनीति कम कर सकते हैं। सरकार की दखलअंदाजी का मैं वायदा कर रही हूँ और पहले भी

ऐसा नहीं हुआ है। सरकार की दखलअंदाजी कम रही है। राजनीति की दखलअंदाजी और उनकी अपनी जो राजनीति है—क्योंकि राजनीति के तो कई स्वरूप होते हैं—जिसके कारण खेल प्रभावित होते हैं, अगर वह कम करनी है तो कोड ऑफ कंडक्ट को लाने में और कन्करेंस को लाने में मुझे सदन के संरक्षण की, सदन के सहयोग की और सभी राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, वह मिलेगा तो हम जरूर लाएंगे। दूसरी बात जो आई है, यद्यपि वह प्रश्न की परिधि के बाहर है लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है और सदन को जानने का अधिकार है इसलिए सदन के अधिकार का सम्मान करते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी क्योंकि यह प्रश्न अचानक अभी उठकर खड़ा हुआ है इसलिए सदन को और देश को भी यह जानने का अधिकार है कि सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है, जो बी०सी०सी०आई० के लोगों ने सवाल उठाया है। मैं इस बात को बाहर रिपीट करती रही हूँ इसलिए मैं बहुत संक्षेप में यहां बताना चाहूंगी कि हम कभी भी क्रिकेट के खिलाफ नहीं रहे हैं। दूसरा, दूसरे खेलों को हमने कभी भी क्रिकेट की तुलना में कम करके नहीं आंका है। क्रिकेट की तुलना में हम दूसरे खेलों को दूसरी श्रेणी का या दूसरे नम्बर का खेल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के प्रति जो आकर्षण नौजवानों के मन में आता है, वह दूसरे खेलों के लिए नहीं आता है। हम प्रयास भी करते हैं, हम कहीं भेदभाव का बर्ताव भी नहीं करते हैं बल्कि हम दूसरे खेलों को फाइनैशियल असिस्टेंस ज्यादा देते हैं ताकि उनको बढ़ावा मिले लेकिन इस देश के जो नौजवान हैं, उनका रुझान ही क्रिकेट की तरफ ज्यादा है और अगर उनका रुझान क्रिकेट की तरफ ज्यादा है तो उस रुझान को तो हम कम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो बायलैट्रल मैचिज़ की बात आयी है, मेरी जो मिनिस्ट्री है, वह नोडल मिनिस्ट्री है—सिर्फ सूचना देने के लिए। कोई टीम बाहर जाने के लिए होती है तो ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से हमें पूछना होता है। कोई टीम बाहर से आती है तो होम मिनिस्ट्री से हमें पूछना होता है इसलिए इस बारे में जो निर्णय हुआ है कि बायलैट्रल मैचिज़ पाकिस्तान के साथ फिलहाल नहीं खेलने हैं, यह निर्णय हमने नहीं लिया है। यह निर्णय विदेश मंत्रालय ने हमें अवगत कराया है और इसे हमने उनको आगे अवगत कराया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बी०सी०सी०आई० के लोग इसमें किस प्रकार की क्लीयरिटी चाहते थे। मैं क्लीयर करना चाहती हूँ कि बायलैट्रल मैचिज़ के अलावा और शारजाह, सिंगापुर और टोरंटो—जो कि क्रिकेट के इरैगुलर वैन्यूज़ हैं—हमने कहा कि इरैगुलर वैन्यूज़ में हमें खेलने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही क्रिकेट के बायलैट्रल मैचिज़ फिलहाल हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने हैं। इसके अलावा हमने बी०सी०सी०आई० को कहीं नहीं रोका है। अगर वह क्लीयर नहीं है तो यह उनकी अपनी परेशानी है, उनके अपना दिमाग इस बारे में क्लीयर रखना चाहिए। मैं तो सदन को इतनी सूचना दे रही हूँ कि जो खेल

आगे होगा, जिसमें लोगों की रुचि होगी, हमारी तरफ से उसे बढ़ावा देने में कोई कठिनाई नहीं होगी लेकिन अगर हमारी अपनी नीति के कारण किसी खेल के बारे में हमें कोई निर्णय करना पड़े तो खेल संघ को हमें सहयोग करना चाहिए, देश को सहयोग करना चाहिए न कि उसका ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि वह पैसा नहीं कमा रहा है। यह सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगी।

DR. KARAN SINGH: Sir, this question is about the action plan for promoting sports. It is a sorry state of affairs that though we represent one-sixth of the human race, our performance in international sports is very poor. We hardly manage to get one bronze medal in the Olympic Games. The point that I would like to ask the hon. Minister is that sports ultimately is based on the physical fitness of our younger generation. Unless you have a national physical fitness campaign, unless you upgrade the physical fitness of our youths, you cannot achieve the best quality in sportsmen. Sportsmen are only the tip of the pyramid. The pyramid has got to be strong. The reply to my hon. colleague's question is simply with regard to the 75,000 people who are benefited. But, unless millions of young people are benefited, you cannot have the desired quality of sportsmen. You have to develop a proper plan for physical training and for yoga. I remember, when I was in the Health Ministry twenty five years ago, we had developed a graded system of yoga for schools. You do not need expensive equipment for that, you do not need expensive gymnasias. All you need is a capacity to develop the capacity. 'शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्' is a well-known saying. I would like to ask the hon. Minister—I am sure, she herself has practised yoga—whether the Government has got any proposal to launch the national physical fitness campaign, to have a campaign to encourage young people to develop strong bodies, muscles of iron and nerves of steel, as Vivekananda had said. It is only when the base is strong that we are going to do well in sports. Otherwise you will only have an occasional genius like Vishwanathan Anand. We will never be able to do well in sports without this.

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य हमारे देश के माने हुए उद्भट विद्वान भी हैं, इन्होंने एक बात कही है और मुझे एक अवसर भी दे दिया है जिसका मैं उपयोग करूंगी। हम लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और फिजिकल फिटनेस की कल्चर पूरे देश में व्यापक हो जाए, इस माहौल को हम निश्चित रूप से क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा देश दुनिया की बहुत

बड़ी आबादी का देश होते हुए भी जब हम ऑलम्पिक और अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी स्थिति देखते हैं तो वास्तव में शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन हमें एक तरफ यह भी देखना पड़ेगा कि उन तैयारियों के लिए हमारी जितनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारी सीमाएं जितनी हैं उनमें हमें दो तरह का सहयोग मिल जाए तो अच्छा है। माननीय सदस्य ने मुझसे यह सवाल कर दिया तो मैं सदन से निवेदन करूंगी कि राज्य सभा के सदस्यों को जो सांसद विकास निधि मिलती है उसमें से वे कुछ जिले गोद ले लेते हैं विकास की दृष्टि से, इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में खेलों के मैदान को बढ़ावा दें, स्टेडियम की बात आखिर में आए। क्योंकि स्टेडियम तो कुछ खास गेम्स के लिए होते हैं इससे कम से कम एक खेल का मैदान तो सुरक्षित हो जाए। उसमें फैंसिंग लग जाए और खेल के कुछ सामान बच्चों को मिल जाएं। अगर इस प्रकार का बढ़ावा राज्य सभा के माननीय सदस्यों की तरफ से अपने सांसद विकास निधि से मिलने लग जाए तो उसका भी एक अच्छा परिणाम सामने आएगा।

सर, एक और अच्छी बात हो गई है और मैं आदरणीय डाक्टर साहब को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यह बात उठा दी। यहां माननीय शिक्षा मंत्री माननीय जोशी जी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमें आश्चस्त कर दें कि वे शिक्षा के बजट का 10 परसेंट खेलों की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए देंगे क्योंकि शिक्षा का बजट इतना बड़ा है कि खेल का बजट उसके मुकाबले ऊंट के मुंह में जिर के बराबर है। इस साल मैं लड़-झगड़कर जो बजट इसके लिए दिला पाई हूँ अगर उसमें से तनख्वाह वगैरह का खर्चा निकाल दें तो 70-80 करोड़ रुपया खेलों को बढ़ावा देने के लिए बचता है, एफ्रो-एशियन गेम्स के लिए जो बजट मिला है उसको छोड़कर। ऐसी स्थिति में अगर माननीय शिक्षा मंत्री आज सदन को आश्चस्त कर दें तो मैं सदन से आग्रह करूंगी कि वह आज शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए मजबूर करें कि वह अपने बजट का 10 परसेंट खेल को शिक्षा का अंग मानकर देंगे तो मैं माननीय सदस्य को यह वचन देती हूँ, इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है, हम अगले दस साल के अंदर भारत को खेल की दुनिया में नम्बर एक पर ला सकते हैं। प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है कमी अगर है तो हमारी तरफ से है। तैयारियों के लिए और प्रोत्साहन के लिए जो बातें होनी चाहिए उनमें कसर रह जाती है। यदि माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय में सदन को आश्चस्त कर दें तो मैं उनकी आभारी रहूंगी ... (व्यवधान) ...

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मैंने अपनी निधि से बुलन्दशहर में स्टेडियम के लिए पैसा दिया है और दो कॉलेजों के मैदान के लिए प्रस्तावित किया है ... (व्यवधान) ...

SHRI SURESH KALMADI: It is an important matter. The Education Minister is here. He should react. कम से कम पांच तक तो कर दीजिए ... (व्यवधान)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): मैंने उनकी बात सुन ली है ... (व्यवधान)...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: The hon. Minister has said that there will not be a bilateral cricket match between India and Pakistan in the present situation. I think the decision is a strange one. There will be every possibility of India facing Pakistan in the ICC knock-out tournament, the World Cup and the Asia Cup matches. I do not know why only bilateral cricket matches India and Pakistan have been banned. But in tri-series and multi-series India has been allowed to play against Pakistan. Why? I want a reply from the Minister on this point.

सुश्री उमा भारती: सभापति महोदय, इस विषय में हमारी नीति स्पष्ट है। आई०सी०सी० नॉक आउट में एशिया कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप, अन्य किसी ट्राईलेटरल मैच में या मल्टीलेटरल मैच में, या भारत और पाकिस्तान बायलेटरल मैच की पोजीशन में आ जाते हैं तो इसके बारे में हमारी राय यह है कि यह होनी चाहिए। लेकिन बायलेटरल मैच के इरादे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक-दूसरे के सामने खड़े हों इस बारे में विदेश मंत्रालय की जो राय है फिलहाल हम उसी राय पर कायम हैं। हम इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसे लेकर न तो कोई उलझन रहनी चाहिए और न ही स्ट्रेन लगना चाहिए।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Would the hon. Minister let us know--in the context of promotion of sports--whether there is any programme for laying astro-turf for hockey at various centres, particularly, for the Junior National tournaments, in the Eastern Zone of the country?

सुश्री उमा भारती: सभापति महोदय, वहां पर हॉकी के एस्ट्रो टर्फ को बिछाने के लिए जो प्रस्ताव आए हैं वे विचाराधीन हैं। बहुत जल्द ही हम इस पर फैसला लेने वाले हैं। वैसे भी माननीय सदस्य का ईस्टर्न जोन से मतलब नॉर्थ ईस्ट से रहा होगा ... (व्यवधान)...

श्री शंकर राय चौधरी: सारी जगहों से है।

सुश्री उमा भारती: सभापति महोदय, इसमें एक परेशानी आ जाती है। हमारी कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसके लिए हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग ग्रांट राज्य से लेनी पड़ती है। कुछ स्कीम्स

ऐसी हैं जिसमें 75-25 का रेशो होता है और कुछ में 50-50 का रेशो होता है। अगर राज्य सरकारें सहयोगी रुख न अपनाएं तो कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं लेकिन हॉकी के एस्ट्रो टर्फ बिछाने के लिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जोन से जिस तरह के प्रस्ताव हैं उन सब प्रस्तावों पर हम विचार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह का रिलेक्सेशन देकर इसे करें। मैं माननीय सदस्य के उत्तर में एक और जानकारी सदन को देना चाहंगी कि अभी जब हमने खेल मंत्रियों की बैठक बुलाई थी उसमें हमने देश में सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने का फैसला लिया है। हम यह अनुभव कर रहे थे कि दूसरे देशों में बालक को बाल्यवस्था से ही तैयारी कराते हैं। हमारे देश में अभी इस तरह की व्यवस्था में कमी थी इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब हर राज्य में एक अकेडमी खुलेगी जो कि ज्वाइंट वेंचर में होगी। इसमें राज्य सरकार होगी पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर होगा और केंद्र सरकार होगी। ये तीनों मिलकर उस अकेडमी को खोलेंगे। राज्य में यह एक अकेडमी होगी और उस राज्य के लोग जिस खेल में नम्बर एक पर होंगे, जिस खेल में निष्णात होंगे यह उसी पर केंद्रित होगी। इसके अलावा दूसरे खेल भी उसमें शामिल होंगे लेकिन यह नम्बर एक वाले खेल पर ही केंद्रित होगी। बच्चे वहीं रहेंगे। वहीं से स्कूल पढ़ने जाएंगे। उनकी पूरे टाइम तैयारी होगी, उनके लिए कोचेज की व्यवस्था कराई जाएगी। उनकी शिक्षा के हिसाब से उनका शेड्यूल और कैलेंडर बनाकर रखा जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ अकेडमीज तो हम इस साल के पूरा होते-होते शुरू कर देंगे और उसका लाभ भी ईस्टर्न जोन को मिलेगा।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं अपने मुख्य सप्लीमेंट्री पर आने से पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान बैडमिंटन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बैडमिंटन के बारे में उन्होंने बताया कि हम क्रिकेट के अलावा और गेम्स में भी इंटरस्ट लेते हैं और प्रमोट करने के लिए एक्शन प्लान भी है। मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलने जाता हूँ। वहां जो कोर्ट है वह बैडमिंटन के लिए स्पेशियली बनाया गया है। वह महीने में बीस दिन किसी और काम के लिए बुक रहता है। ऐसे कामों के लिए—जिनके बारे में कहना कोई अपमानजनक बात नहीं होगी, जैसे कभी देवीलाल जी की श्रद्धांजलि सभा हो गई, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है तो तीन दिन के लिए बंद हो गया, कभी बी.जे.पी. की एकजीक्यूटिव मीटिंग चल रही है आदि। यह बैडमिंटन कोर्ट है, आपकी अकेडमी है, अकेडमी में लड़के हैं, वहां कोचेज है। अगर आप कोर्ट नहीं देंगे तो वे बच्चों को कैसे सिखाएंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि हमें कम से कम एक परमानेंट कोर्ट दीजिए जिससे हम बच्चों को पूरे तीस दिन बैडमिंटन सिखा सकें। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी बैडमिंटन कोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है, खेल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जो उसका उपयोग हो रहा है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए पूछना चाहूंगा कि क्या इस दुरुपयोग को आप सदुपयोग में बदलेंगी? दूसरा

जो मेरा सप्लीमेंटरी है वह यह है कि एफ्रो-एशियन गेम्स के संदर्भ में पूरा देश जानता है कि पहले माननीय मंत्री महोदया ने इस गेम के आयोजन को रोक था यानी आपने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मेरे दिमाग में प्रश्न है कि पहले क्यों आपने अनुमति नहीं दी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में अपनी तरफ से दखल दी तब इसकी अनुमति दी कि भारत सरकार को इसका आयोजन करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अनुमति दी उसकी पीछे क्या लाजिक था? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि एफ्रो-एशियन गेम्स के आयोजन के लिए भारत सरकार की तरफ से कितना खर्च हो रहा है और इसमें पूरा खर्चा कितना होगा और आप के मंत्रालय का कितना खर्च हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एफ्रो-एशियन गेम्स के आयोजन के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्या वह हमारे पास उपलब्ध है? क्या एथलीट्स के लिए जो ट्रैक्स होते हैं, ये ट्रैक्स उस लेवल के हैं, उस स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं? हाकी के लिए जो एस्ट्रो-टर्फ चाहिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए क्या उस स्तर का एस्ट्रो-टर्फ आपके पास है?

सुश्री उमा भारती: माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे दो सप्लीमेंटरी हैं। लेकिन उनके सप्लीमेंटरी में हिडन सवाल 6-7 हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि स्टेडियम का दुरुपयोग दूसरे उद्देश्य से होता है। हमारी दिक्कत यह है कि एशियाड के वक्त जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था यह हमारे लिए सफेद हाथी हो गया है। इसको मेंटेन करने के लिए बजट धनराशि अपर्याप्त होती है। इसलिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें दूसरे उपाय अजमाने पड़ते हैं। कोशिश तो हमारी यह रही है कि खेलों के जरिए ही रेवेन्यू जनरेट हो और दूसरे फैडरेशन अपनी प्रतिस्पर्धाओं के लिए हमारे स्टेडियम का उपयोग करें। लेकिन इस ओर कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए यह फैसला करना पड़ा कि दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी हम उसका उपयोग करें। माननीय देवी लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो कार्यक्रम हुआ वह बहुत व्यवस्थित था और ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि पहुंचती है तब जब फिल्म स्टार नाइट जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके कारण दिक्कत रहती है।

श्री संजय निरुपम: मैं हानि की बात नहीं कह रहा हूँ। यह बैडमिंटन स्टेडियम है इसलिए इसका उपयोग केवल बैडमिंटन खेलने के लिए ही होना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसलिए या तो आप ऐसा करें कि वहां केवल बैडमिंटन ही खेला जाए अन्यथा अकेडमी को दूसरा बैडमिंटन कोर्ट बनाकर दीजिए, जहां बच्चे महीने में तीस दिन लगातार खेल सकें, अपनी ट्रेनिंग ले सकें।

सुश्री उमा भारती: सर, मैं माननीय सदस्य की पहली बात का उत्तर देने जा रही थी। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक फिल्म स्टार शो के बाद देखा कि उस शो से काफी हानि

पहुंचती है तो उसके बाद मैंने एक बैठक बुलाई और इसके लिए एक कमेटी बनाई। वह कमेटी बहुत जल्द इस बारे में अपनी रिपोर्ट देने जा रही है कि स्टेडियम में जो दूसरी ऐक्टिविटीज होती हैं उससे कितनी हानि होती है और यह स्टेडियम जिस मूल पर्पज के लिए बना तो यह पर्पज कहीं इससे डैमेज तो नहीं होता। अगर यह रिपोर्ट ऐसी आई तो हम तय कर लेंगे और खेलों के अलावा दूसरी ऐक्टिविटीज हम लगभग नहीं होने देंगे। इस प्रकार का हम एक फैसला कर लेंगे और यह फैसला हम बहुत जल्दी करने वाले हैं।

दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है वह यह है कि हम कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या तैयारी कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने फैसला किया है कि एफ्रो-एशियन गेम्स के लिए 35 करोड़ तो हमको सरकार की तरफ से बजटरी सपोर्ट के रूप में मिला है और 15 करोड़ रुपया हमने संसाधनों से जुटाया है। इस प्रकार 50 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से एफ्रो-एशियन गेम्स में होने वाले खर्च के लिए होगा और 20 करोड़ रुपया आईओए के चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं, श्री कलमाडी जी, उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ रुपया वह अपनी तरफ से इसमें लगावेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है कंडक्ट आफ गेम्स। दोनों को मिलाकर 70 करोड़ रुपया होने की बात आई है और इस हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। इसमें 20 करोड़ रुपए का कमिटमेंट आईओए से है और 50 करोड़ रुपया हमने अपनी तरफ से जुटाया है जिसमें बजटरी सपोर्ट हमें 35 करोड़ का मिला है। इसके अलावा उन्होंने बात पूछी है कि कुछ ट्रेक ऐसे हैं जिनके बारे में निश्चित तौर से यह बात थी कि उनकी रिपेयर हो नहीं सकती, यह बिल्कुल असंभव है, इसलिए इसको नए तरीके से लिया जाए। उसके बाद बात आई कि शायद रिपेयर से काम नहीं चलेगा इसलिए ले लिया जाए। इसलिए एक नई तैयारी चल रही है। लेकिन हम वही करेंगे जो खेलों और खेल की प्रतिष्ठा के हित में होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास सीमित समय है, उसमें हम जो कर सकें वह करें। अभी फिलहाल हम आईओए के परामर्श से हमारी जो अपनी इंटरनल फाइनेंस कमेटी है, उसके साथ बैठकर इन सारी चीजों पर फैसला लेते हैं। ट्रेक के बारे में हम कोई क्लियर फैसला लेकर जल्दी आ जायेंगे। एफ्रो-एशियन गेम्स की जो बात है, 1988 से हमारे देश में गेम करने के बारे में मामला पड़ा हुआ है। पिछले साल क्योंकि आर्गनाइजिंग कमेटी बनने में देर लगी इसके कारण मुझे लगा कि इस वर्ष यह नहीं हो पायेंगे। इसलिए अगले वर्ष के लिए हमने इसे डिफर कर दिया। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्रीजी को लिखा कि इसे डिफर किया जाए। उन्होंने डिफरमेंट को अप्रूव किया। लेकिन बाद में जब सभी खेल संगठनों ने जाकर प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाकर निर्देश दिया कि भले ही समय कम है लेकिन अगर तैयारी हो सकती हो तो गेम कर लेने चाहिए। मैंने उनके सामने अपनी कठिनाई बता दी और यह कहा कि समय कम है और यह खेल करना हिमालय की चढ़ाई चढ़ना जैसे होगा।

लेकिन मेरे अन्दर यह आत्मविश्वास था, अपने अधिकारियों पर भरोसा था कि हम तैयारी कर लेंगे। इसलिए खेल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। सदन की भी इच्छा थी। देश के लोगों की भी इच्छा थी। इसलिए खेल होंगे। मुझे लगता है कि बिना किसी बाधा के राष्ट्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप हम खेल कर पाएंगे।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELIGATION FROM YEMEN

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from Yemen, currently on a visit to our country, under the distinguished leadership of His Excellency, Sheikh Abdulla Bin Hussein Al-Ahmar, Speaker of the House of Representatives of the Republic Yemen.

On behalf of the Members of the House, and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary System, our country, and our people and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Yemen. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Yemen.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—(Contd.)

*603. *[The Questioner (Shri Vijay Singh Yadav) was absent. For answer vide page 30 infra.]*

*604. *[The Questioner (Prof. M. Sankaralingam) was absent. For answer Vide page 31 infra.]*